(b) if so, what steps are taken by Government to establish more gas based fertilizer industrial units;

(c) whether thert is any gas based fertilizer industrial unit in the southern States like Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka and Pondicherry;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, what steps are being taken by Government to establish gas based fertilizer industries in south-States?

THE MINISTER OF STATE IN THE. MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) It is a fact that a gas based fertilizer plant gives lowest cost of production as compared to plants based on other feedstocks like coal, naphtha, fuel oil etc.

(b) to (e) Subject to availability of gas, a few projects for setting up gas-based plants have been identified for implementation during the Eighth Plan. Except in Andhra Pradesh, where a major gas-based fertilizer plant is presently under implementation in Kakinada, there are no gas based fertilizer plants in other Southern States: Similar projects in other Southern States can be taken up when gas availability is confirmed.

Setting up of new Oil Refinery

@1467. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new modern integrated solvent extraction and oil refinery project is being set up in the country; and

(b) if so, the details thereof including its location, cost, production capacity and date of commencement and completion?

©Previously Unstarred Question 678, transferred from the 15th July, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) In do far as the vegetable oil sector is concerned the activity relating to setting up of new modern integrated solvent extraction and oil refinery project is delicensed. Any way, no such proposal has been received in this Ministry.

(b) Does not arise.

आदिवासियों के लिए उचित दर की दुकानें

*1468. श्री शिव प्रसाद जनपरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के मुख्यालय में उचित दर दुकानें खोल कर वितरण की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूखाग्रस्त पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी अभी भी इस वितरण व्यवस्था के लाभों से वंचित तथा उन्हें इन क्षेत्रों में 15–15 किलो मीटर दूर तक भटकने के बाद भी इन दुकानों से अनाज नहीं मिल पाता ;

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं को वितरण व्यवस्था के लाभों से वंचित करके लाभ कमाने में लगी हुई इन वितरण एजेंसियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ; और

(घ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी पंचायतों में दुकानें खोलने के प्रावधान का अनुपालन/कार्यान्वयन किया गया है तथा इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार

ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे चुने हुए क्षेत्रों में जहां यह सुविधा कम है/नहीं है, अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलें । उन्हें यह भी सलाह दी गई हैं कि उचित दर की दुकानें इस तरीके से खोली जाएं कि लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों से अपनी आपूर्ति लेने के लिए लम्बी दूरी तय न करनी पड़े । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आंतरिक वितरण जिसमें अन्तर-जिला, अन्तर क्षेत्र शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आवंटन शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है । चुने क्षेत्रों में 9159 अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोली गई हैं ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है । राज्य प्रशासन के अधिकारी अनुचित व्यापारिक पद्धतियों को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को खुले बाजार में भेजे जाने से रोकने/पता लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता पर नजर रखने हेतु उचित दर की दुकानों की विकसित रूप से जांच करते हैं तथा उनका दौरा करते हैं । राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्ध के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर आपूर्ति तथा उपलभ्यता की नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है । राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना भी नियमित रूप से दी जाती है ।

(घ) उचित दर की दुकानें विशिष्ट रूप से जवाहर योजना के लिए नहीं खोली जाती है । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं कि उन सभी ब्लाकों में जहां संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है, वहां जवाहर रोजगार योजना के तहत आंशिक मजदूरी के रूप में खाद्यान्न का वितरण केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए किया जाए ।

Demand for various commodities

1469. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the demand for various commodities received from the State Governments during the last 12 months; and

(b) the commodities provided to them during the same period month-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES. AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Promotion of employees in stenographic service

1470. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER foe pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Deptt, of Personnel and Training has received a number of cases for clarification from different Ministries/ Depots. | Statutory | Autonomous Bodies since 1st March, 1992 regarding restoration of inter-se seniority of their employees of General Category vis-avis S.C. & S.T. Category due to wrong application/interpretation/ implementation of, Reservation Rules while promoting their employees in Stenographic Service;

(b) if so, the number of such cases from different Organisations;

(c) whether it is a fact that the Deptt. of Personnel and Training has not clarified the points raised in cases referred to it; and

(d) if so, what steps are being taken to expedite such cases?